

क्रान्ति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 27, 17 अक्टूबर, मंगलवार 2017, सूत, हिन्दी दैनिक

9879141480

4 ओ बर्बाक आगम नवकार कॉम्पलेक्स, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूत-गुजरात

सार समाचार

जुता कारोबारी से 72 किलो पटाखे बरामद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद पटाखों की बिक्री करने वाले कारोबारियों पर पुलिस को कार्रवाई जारी है। पूर्वी जिला पुलिस ने शनिवार को मंडवल्ली में एक जुता कारोबारी के घर से लगभग 72 किलो पटाखों बरामद किया है। केस दर्ज कर पुलिस ने कारोबारी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसने पटाखों की बिक्री के लिए अरुणा लाइसेंस लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद खरीद-फोख पर रोक लगा दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पटाखों कर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को यह जानकारी मिली थी कि मंडवल्ली के सेंट्रल मार्केट में रोड में जुता कारोबारी मनमोहन जुते बेचने की आड़ में पटाखे बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने कारोबारी की दुकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया। पुलिस पटाखों में आरोपी ने बताया कि दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए उसने अरुणा लाइसेंस लिया था। लाइसेंस मिलने पर उसने पटाखे खरीदे थे और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी वह पटाखे बेचना रहा।

शत्रु का वार: कहा-गुरदासपुर लोकसभा उप चुनाव में इस्लामि मिली हार

नई दिल्ली। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में पार्टी को मिली करारी हार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दबीर पर कांग्रेस को जीत की बधाई देते हुए पार्टी पर तंज करते हुए एक के बाद एक छह ट्वीट किए हैं। भाजपा सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जैसी उम्मीद थी, गुरदासपुर उपचुनाव में पार्टी को करारी दो लाख वोटों के अंतर से अग्रगण्यता हार मिली है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि उन्हें पहले से ही जो उम्मीद थी क्योंकि लोकप्रिय और महान ख्याति विनोद खन्ना के करीबी को उप चुनाव का विजय नहीं दिया गया। गुरदासपुर की संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के उम्मीदवार को दो लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। आपकी खाना दें कि भाजपा के बरिष्ठ नेता विनोद खन्ना के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी।

ट्रेन की चपेट में आकर एएसआई की मौत

सास का हालचाल पूछने ससुराल जा रहा एएसआई
नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी भागा इलाके में हेली पुलिस के एक एएसआई को रेलवे लाइन पर कार के समर्थ ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। मृत एएसआई की पंचवत्स पूरा पुलिस लाइन निवासी ओम प्रकाश (54) के रूप में हुई। मृत पुलिसकर्मी मूलरूप से पंजाब का रहने वाला था और हासिल के एक वह अपने ससुराल जा रहा था। मौक पर पहुंची पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है मामला दर्ज कर हादरे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश 1982 में दिल्ली पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल भर्ती हुए थे और कई साल की नीकरी में पदोन्नति पाकर बतौर एएसआई राजेंद्र नगर थाना इलाके में पोसीआर में तैनात थे। उनका ससुराल दिल्ली के तारा नगर इलाके में है। उनकी सास की काफ़ी दिवस से तबीयत खराब थी। शनिवार शाम साढ़े चार बजे वह अपनी सास का हालचाल जानने के लिए ससुराल जा रहे थे। रास्ते में सब्जी मंडी स्थित रेलवे लाइन पर कार के समर्थ तेज रफ़्तार ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। **पिस्टल के बल पर साढ़े छह लाख रुपए लूटे**

नई दिल्ली। फर्रुख बाजार थाना इलाके में हथियार बंद बाइक सवार बदमाश एक सड़क से पिस्टल के बल पर साढ़े छह लाख रुपए लूटकर पसार हो गए। पॉइंट की पंचवत्स मंडी निवासी रामने (45) के रूप में की गई है। पॉइंट की शिकाफार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पॉइंट के मुताबिक रामने मंडोली स्थित सुबो चौबीस नामक राइफ़ की कम्पनी में कार्यरत है। शनिवार को उसके माफिक ने उसे थियान नगर से 7 लाख रुपए का कैश केस लेकर घर लाने के लिए कहा था। रामने अपनी स्कूटी से थियान नगर गया और सतपाल भूटानी से प्राप्त साढ़े छह लाख रुपए का भूतपाल बैग में रखकर मंडोली लौट रहा था। बीच रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने पता पूछने के हारे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामने को उनकी मंशा पर शक हुआ और उसने स्कूटी पास ही किसी परिचित की फेक्टरी के सामने रोक दी,

राहुल गांधी दिवाली के बाद अध्यक्ष का नामांकन करेंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम जल्द घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देंगी। कांग्रेस चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी।

पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री रामवर्मा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव का संभावित कार्यक्रम सौंप दिया है। वह चाहते हैं कि 30 अक्टूबर तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। हालांकि, उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यू इस कार्यक्रम में बदलाव कर सकती है। कांग्रेस संविधान

के मुताबिक, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन के लिए सात दिन का वक दिया जाएगा। इसके बाद एक दिन नाम वापसी के लिए दिया जाएगा। चुनाव प्राधिकरण के एक सदस्य ने कहा कि यदि अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक नामांकन दाखिल किया जाता है, तो भी निर्वाचन चुने जाने की औपचारिक घोषणा नाम वापस लेने का बख्त खत्म होने के बाद ही की जाएगी। पार्टी की अधिकतर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारणी और एआईसीसी के सदस्यों के चयन का अधिकार पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया है। चुनाव प्राधिकरण के एक सदस्य ने कहा कि केरल को छोड़कर सभी प्रदेशों में प्रस्ताव भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के

कांग्रेस में फेरबदल:

कांग्रेस में फेरबदल:

सदस्यों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। एक-दो दिन में पीसीसी सदस्यों के नाम पर भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव में पीसीसी सदस्य ही मतदाता मंडल में शामिल होंगे हैं।

मंडोली कर्नाटक कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष बने
कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मंडोली को कर्नाटक कांग्रेस घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष और नीपल शंकर को उपअध्यक्ष बनाया है। इस समिति के गठन को पार्टी उपअध्यक्ष राहुल गांधी ने मंजूरी दे दी है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मारिट अल्ला समेत 33 सदस्य होंगे। कर्नाटक में 2018 के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की 224 सदस्यीय मौजूदा विधानसभा का कार्यक्रम 28 मई 2018 में समाप्त हो रहा है। तत्कालीन कांग्रेस जहां



कर्नाटक में अपनी सफलता को दोहराने के प्रयासों में जुटी है, वहीं भाजपा उससे चुनाव में सत्ता छीनने के प्रयासों में लगी है। राहुल ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की कार्यसमिति को भी मंजूरी दे दी है इसमें

94 सदस्य होंगे। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया, पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों, एआईसीसी के पदाधिकारियों, राज्य के पार्टी सांसदों और अन्य नेताओं को सदस्य बनाया गया है।

दिवाली से पहले थोक महंगाई दर में कमी, फिर भी प्याज, अंडा और मीट हुआ महंगा

नई दिल्ली। दिवाली से पहले आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार की ओर से राहत की खबर आई है। सितंबर 2017 में थोक महंगाई दर घटकर 2.60 फीसदी पर आ गई। अगस्त में यह 3.24 फीसदी पर था, जो कि चार माह के सबसे ऊंचे स्तर पर था। सितंबर महिने में सर्ववर्गीय के दाम 15.48 पर पहुंच गए हैं। अगस्त में ये 44.91 के स्तर पर था। थोक महंगाई में लगातार दो माह की तेजी के बाद पहली गिरावट दर्ज की गयी है। अगस्त में यह चार महिने के उच्चतम स्तर 3.24 प्रतिशत पर रही थी। इससे पहले वही माह में यह 1.88 प्रतिशत रही थी। पिछले साल सितंबर में थोक महंगाई दर 1.36 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। सरकार द्वारा आज यहाँ जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में भाजपा प्रशास्य के दाम 2.04 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़े हैं। इस श्रेणी में महंगाई दर कम रहने का मुख्य कारण दालों के दाम एक साल पहले की तुलना में 24.26 प्रतिशत और आलू के 46.52 प्रतिशत घटना रहा है। गेहूँ की कीमतों में 1.71 प्रतिशत और मोटे अनाजों में 0.07 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

सखियों के दाम घटने का मिला फायदा

सितंबर में थोक महंगाई दर कम होने में सखियों के दाम में आई कमी ने सहाय दिया है। पहली दर महिने आधार पर सितंबर में खाने पीने की चीजों की थोक महंगाई दर 1.99 पर आ गई है। इससे पहले महिने यह 4.41 फीसदी पर था। सितंबर 2017 में फूड इन्फ्लेशन की थोक महंगाई दर गिरकर 2.04 फीसदी रह गई, जो अगस्त में 5.75 फीसदी थी। थोक महंगाई दर में फूड इन्फ्लेशन की हिलचलें 15.26 फीसदी हैं। सितंबर में सखियों के दाम गिरें हैं। सखियों की थोक महंगाई गिरकर 15.48 फीसदी पर थी। फली की थोक महंगाई भी पिछले महिने गिरकर 2.93 फीसदी पर आ गई जो अगस्त में 7.35 फीसदी थी।

प्याज, अंडा, मीट हुआ महंगा

हालांकि प्याज के दामों में सितंबर में राहत नहीं मिली। सितंबर महिने में प्याज के दाम 79.78 फीसदी के स्तर पर पहुंच गए। वहीं, अंडे, मीट और मछलियों के दाम 5.47 फीसदी के स्तर पर रहे। अंडा, मीट, मछली के दाम बढ़े सितंबर में प्रोटीन प्रोड्यूसर अंडा, मीट और मछली की थोक महंगाई बढ़ी है। सितंबर में इसकी महंगाई दर 5.47 फीसदी रही, जो अगस्त में 3.93 फीसदी रही। मिमरल्स की महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महिने मिमरल्स की थोक महंगाई दर -7.73 फीसदी दर्ज की गई, जून में यह आंकड़ा 24.84 फीसदी पर था। आलू, दाल और गेहूँ की थोक महंगाई सितंबर में भी शून्य से नीचे बनी रही। यह क्रमशः -46.52 फीसदी, -24.26 और -1.71 फीसदी दर्ज की गई।

ईंधन के मोर्चे पर भी मिली राहत

ईंधन और पावर सेक्टर की बात करें, तो यहाँ भी महंगाई से राहत मिली है। सितंबर महिने में इस सेक्टर के लिए महंगाई 9.01 फीसदी पर रही। अगस्त में यह 9.99 फीसदी रही। पेट्रोल के थोक दाम गिरें लेकिन एलपीजी के बढ़ें हैं। पेट्रोल की महंगाई अगस्त के 24.55 फीसदी के मुकाबले सितंबर में 15.79 फीसदी रही। वहीं, एलपीजी की महंगाई अगस्त के 5.33 फीसदी की तुलना में सितंबर में बढ़कर 20.75 फीसदी हो गई है।

दाल की कीमतों में कमी

वहीं दलहन के दाम सितंबर में 24.26 नुचे आ गए। आलू की कीमतों में 46.52 नुचे आ गईं। मसूर की गिरावट दर्ज की गई। मसूर के फेब्रिकरी सेक्टर की भी मिली राहत मैयूफेब्रिकरी सेक्टर के लिए थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं मिली है। सितंबर में मैयूफेब्रिकरी सेक्टर की थोक महंगाई दर 2.45 फीसदी से बढ़कर 2.72 हो गई है। अगस्त में चार महिने के उच्च स्तर पर पहुंची थी दर थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फाति आसर्ष में चार महिने के उच्चस्तर 3.24 नुचे पर पहुंच गई थी।

पाक पर वार: नायडू बोले, आतंकवादियों को सहायता देना पड़ोसी देश की नीति

नयी दिल्ली मानेसर। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि वह सोसा पाक आतंकवाद को एक नीति के रूप में बढ़ावा दे रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस तरह की नीति अपनाने वाले देशों को अलग-थलग कर देना चाहिए। उप राष्ट्रपति ने हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 33 वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा, 'हमारे पड़ोसी ने आतंकवादियों को सहायता, धन मुहैया कराने और प्रशिक्षण देने को अपनी नीति बना लिया है।' उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट हो जाए।

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता
नायडू ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तथा न ही वह सोसाओं से बंध है और किसी को भी विचारधारा के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में पुरुषा बुद्धिमाय जाकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की सूचनाएं गोला बारूद तथा हथियारों पर भी भारी पड़ती हैं। उन्होंने कहा, 'भारतसिंता तथा जवाबदेही जरूरी है। कई बार पुख्ता



जानकारी हथियार और गोला बारूद पर भी भारी पड़ती है।'

एनएसजी कमांडों ने रोक कई आतंकी हमले

देश की सुरक्षा में सहायता योगदान के लिए एनएसजी को प्रशंसा करते हुए नायडू ने कहा कि पिछले तीन दशक में भी अधिक समय से बल के दमक आतंकवादी हमलों तथा विमान अग्रण जैसी घटनाओं से बखूबी निपट रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर पर हमले, मुंबई आतंकवादी हमले तथा पठानकोट पर आतंकवादियों के हमले के दौरान एनएसजी कमांडों की कार्रवाई को देश

कभी नहीं भुला सकता।

आतंकवाद से निपटने के लिए नई रणनीति की जरूरत

उन्होंने कहा कि आतंकवाद की चुनौती बहुत बड़ी है और इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति और तरीकों को नयी धार देनी होगी। राज्य पुलिस बलों को भी मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि एनएसजी पुलिस बलों की प्रशिक्षण देकर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नायडू ने इस मौके पर एनएसजी का पोस्टल कवर भी जारी किया।

करौड़ों की कीमत वाले सामों के साथ खीरी से तीन गिरफ्तार

लखीमपुरखीरी। उत्तर प्रदेश के खीरी जिले की धौरहा पुलिस ने दुर्लभ दोमूहा सांप के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तस्कर दोमूहा सांप बरामद किया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर इस अप्रैरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बरामद दोमूहा सांप की संख्या सांघ भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अंतराष्ट्रीय लक्ष्यी बाजार में इस सांप की इतना करोड़ों में होती है। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे इस सांप को नेपाल बेचने से जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस सांप का वजन लगभग डेढ़ किलो है। इस सांप की अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 से 25 करोड़ रुपये है। गिरफ्तार सांप के तस्करों ने बताया कि वे 8 लाख रुपये में इस सांप को नेपाल बेचने जा रहे थे। बहरादृष्ट के जंगलों में सांप की ये दुर्लभ प्रजाति पायी जाती है।

पाट ने कहा कि सीबीआई अपने कामकाज के कारण ही ऐसी बातें सुन रही है। पाट ने जांच एजेंसी से कहा है कि वह नजीब के लापता होने के संबंध में नौ सौंदर्य छात्रों के कॉल डेटा विश्लेषण के जरिए क्या पता चला है इसकी रिपोर्ट उसे सौंपे।

बाता दें कि सीबीआई ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि सदियों के भेन कॉल और संदेशों का विश्लेषण किया जा रहा है जबकि अपनी मौखिक दलील में कहा था कि सभी रिपोर्टें का विश्लेषण पूरा हो चुका है। जांच एजेंसी की बातों में इसी विरोधाभास को लेकर अदालत बहुत नाराज है। अदालत ने इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, 'फिर आपने बताया क्यों नहीं कि विश्लेषण में क्या मिला है।' पाट ने सीबीआई को चेतावनी में पेश होने की करणी। गौरतलब है कि अदालत लापता छात्र नजीब की मां फातिमा फाफीस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फातिमा ने अदालत से अनुरोध किया है



कि वह जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से 15 अक्टूबर, 2016 को

लापता बेटे का पता लगाने के लिए आदेश जारी करें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगाई डांट,

नजीब मामला:

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी (जेएनयू) के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सीबीआई को डांट लगाई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने कम दिलचस्पी दिखाई और जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। गौरतलब है कि मामले की जांच पंच नजीब ने पेशे CBI को सौंपी गई थी। एम. एसजी वायोटेक्नोलॉजी का छात्र नजीब (27) जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से 15 अक्टूबर, 2016 को लापता हो गया था। घटना से एक रात पहले नजीब की संप परिवार से जुड़े छात्र संध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ झड़प हुई थी। न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सीबीआई के दोषन कहा कि सीबीआई द्वारा मौखिक रूप से दोसरे जानकारी और

सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में विरोधाभास से वह बहुत नाबुख हैं। यह विरोधाभास मामले में सौंदर्य छात्रों के फोन कॉल और संदेश के विश्लेषण के आधार पर सीबीआई द्वारा दी गई स्थिति रिपोर्ट में है। जब अदालत को बताया गया कि स्थिति रिपोर्ट सीबीआई के निरीक्षक द्वारा तैयार की गई थी तब पाट ने कहा कि जांच की जिम्मेदारी एजेंसी को सौंपने वाला 16 मई के उसके आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति डीआईजी के अधिकारों को जांच की निगरानी करनी थी। अदालत ने कहा, 'यह कैसी निगरानी है? अगर यह डीआईजी की निगरानी है तो बिना निगरानी के क्या होगा? उन्हें शायद (कार्यालय में) रिपोर्ट पढ़ने का भी बक नहीं मिला। उन्हें यहां आकर, इसे पढ़ने दें। पाट ने कहा कि सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में काफी कुछ था। हमारा कहना है कि इसमें सीबीआई की दिलचस्पी का पूर्ण अभाव रहा है। दोनों ओर से कोई परिणाम नहीं है। कामकाज पर भी कोई परिणाम नहीं है।'

पाट ने कहा कि सीबीआई अपने कामकाज के कारण ही ऐसी बातें सुन रही है। पाट ने जांच एजेंसी से कहा है कि वह नजीब के लापता होने के संबंध में नौ सौंदर्य छात्रों के कॉल डेटा विश्लेषण के जरिए क्या पता चला है इसकी रिपोर्ट उसे सौंपे।



कि वह जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से 15 अक्टूबर, 2016 को

लापता बेटे का पता लगाने के लिए आदेश जारी करें।

आपी-अपूरी जांच का हसिला जो मनुष्य दूसरों के व्यवहार से ऊबकर ढाण-प्रतिधाण अपने मन बदलते रहते हैं, वे दुर्बल हैं। उनमें आत्मबल नहीं है—सुभाष चंद्र बोस

गौवमयी इतिहास

पटना विविद्यालय (पीयू) के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विविद्यालयों के बीच बेहतर बाने की प्रतियस्धी भाव पैदा करने और उन्हें विश्वस्तरीय बनाने का जो आह्वान किया उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पटना विविद्यालय का गौरवमयी इतिहास रहा है, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा। लेकिन यह भी सच है कि पटना सहित ऐसे अनेक विविद्यालयों, जिनका इतिहास गौरवमयी रहा है और आज भी वे अच्छे काम कर रहे हैं, में से कोई भी विश्वस्तरीय सूची में शामिल नहीं हो पाते। आखिर इसका कारण क्या है कि फोर्ब्स पत्रिका हर वर्ष जिन 500 विविद्यालयों की सूची प्रकाशित करती है, उनमें भारत कहीं नहीं होता? यह एक विचारणीय विषय है और प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाकर उस ओर बहने का आह्वान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीयू को केंद्रीय विविद्यालय का दर्जा देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने साक्षर सने थे। किंतु उन्होंने यह कहकर कि अब इससे आगे सोचने का समय आ गया है पूरे देश को नई दिशा में विचार करने की प्रेरित किया है। किंतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ विविद्यालयों में शामिल होने के लिए क्या कुछ करना होगा, यह ज्ञानदा अहम है? सबसे पहले तो यह स्वीकार करना होगा कि हमारे न्यादार विविद्यालय घिसी-पिटी शिक्षा देने के माध्यम बनकर रह गए हैं। छात्रों को नई दिशा में सोचने की प्रेरणा देने, उन्हें आविष्कार करने योग्य बनाने और उनके अनुरूप अपना आधारभूत ढांचा विकसित करने का माहा उपाय विविद्यालय खो चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी विविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनने के लिए प्रतिस्पर्धी बननी होगी। वस्तुतः केंद्र सरकार का एक योजना है, जिसके तहत व्यावसायिक रूप से सप्ताह 20 वर्षाति (10 सप्ताह) और 10 निजी क्षेत्र के) विविद्यालयों को अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पीयू के समानांतर से इस आह्वान के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि अनेक विविद्यालय इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएंगे एवं वे भीतम में विश्वस्तरीय होने का गौरव भी पा सकेंगे। हालांकि ऐसा करके समय हरा यह भी सोचना होगा कि भारत को जो अपनी मौलिक शिक्षा संबंधी सोच एवं इस पर आधारित पणाली रही है, उसे भी विश्व के समान रखें। केवल विश्व का अनुकरण करने की जगह विश्व को कुछ देने लायक भी बनने का विचार हमारे अंदर इस प्रतियस्धी द्वारा पैदा होना चाहिए।

“न्यू इंडिया”

राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन एवं सम्मान दोनों अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उद्घाटन सत्र में उनका जोर इस बात पर था कि राज्यपाल सलाहकारों की पंक्तिता को बकवर रखते हुए सम्मान में बदलाव के वाक्य दें। उनका यह भी कहना था कि राज्यपाल “न्यू इंडिया” के संकल्प को जनतादोलन का स्वरूप प्रदान करने से लिए छात्रों एवं शिक्षकों को जोड़ सकेंगे हैं। राज्यपालों के संघर्ष में पहली भूमिका को लेकर भी समय-समय पर विवाद उत्पन्न रहे हैं और दूसरी भूमिका के बारे में तो राज्यपाल शाव्य सोचते भी नहीं हैं। वे मानकर चलेते हैं कि यह सब काम केवल निर्वाचित सरकारों और उसके माहता का काम करने वाले सरकारों कीर्तियों का है ही। हालांकि 2022 तक, “न्यू इंडिया” के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यपालों को छात्रों और शिक्षकों से संवाद कर इसे एक जनतादोलन बनाने में भूमिका निभाने की उनकी अपील पर किताब अमम होगा यह देखना होगा। लेकिन सम्मान सत्र में उन्होंने यह कहकर कि से सुभासन की बहम को छेड़ें है कि जिन राज्यों में सुभासन है वे बेहतर कर रहे हैं और जहां सुभासन नहीं है वे राज्य पिछड़े हैं। वास्तव में यह बात सच है कि भारत में विचारों, संसाधनों और क्षमताओं की कमी नहीं है लेकिन सुभासन के अभाव में इतका उपयोगी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता एवं वे राज्य हर दृष्टि से पिछड़े रह जाते हैं। सभी आर्थिक पास सारे संसाधनों हार गमश ठीक नहीं हो, वह कंतिपत्य से होने वाले ध्वनि और साधु प्रदूषण के चलते देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली-आंध्रपास के इलाकों में 1 नमबर तक पटखों की बिक्री को रोक लगाने का फैसला किया है। अदालत यह देखना चाहती है कि दीपावली के आसपास पटखों पर रोक से प्रदूषण के तहत में किन्हीं दीपावली के रोक से? देखा गया है कि दीपावली के बाद वायु और ध्वनि का प्रदूषण खतरनाक तत्तर बढ़ जाता है। पिछले साल दीपावली के दूसरे दिन पटखों की स्थिति किन्ती भयावह थी, यह किसी से छुपा नहीं है। पर्यावरण को लेकर हम किन्ते संजोदा हैं, यह भी जनाजाहिर है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत के निर्णय पर अमल करने के

सत्संग

साधना

भारतीय जीवन-दर्शन में उत्सव और पर्व का विशेष महत्त्व है। उत्सव हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। बाकायदा यह करना उचित होगा कि हम अपने प्रत्येक कर्म को उत्सव के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। उत्सव से उत्साह है और उत्साह में ही जीवन का मर्म छिपा है। इसी तरह कार्तिक मास में अमावस्या के दिन दीपोत्सव हमारी परंपरा है। हमारे सभी त्योहारों में दीपोत्सव का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दीपोत्सव में सभी घरों में दीये जलाए जाते हैं, जिससे कार्तिक माह की घणघोर अमावस्या की रात दीनों की रोशनी से जगमगा उठती है। इस तरह इन दीयों से निकलने वाला प्रकाश हमसे विश्व में शांति व भाईचारे का संदेश देता है। दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिन है। यानी दीपोत्सव किं अंधे से प्रकाश की ओर तो जाने का पर्व है। हमारा उदात्त विषय है कि हमें अंधकारात्मक अमृत्य पर भाव होना चाहिए और अंधे से हम लयके बंध हैं और अंधस के साथ दीपोत्सव मनाते हैं। चौदह वर्ष तक वन में भक्तों और तरे-तरे के ऋषि भोगों वाले श्रीराम के हाथों रावण का वध असत्य पर सत्य की जीत है। इसअसत्य, दीपोत्सव मनाते में मुख्य उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को मन में ज्ञान के प्रकाश की प्रज्ज्वलित दीयों में, ताकि हर चेहरे पर सत्यमान आ सके और सभी मनुष्यों के जीवन में सुख-शांति स्थापित हो सके। मनुष्य के जीवन में अंधे रह जाने हैं और जैसे-जैसे इन सभी स्तरों पर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तो मनुष्य के जीवन से अंधकार मिटता चला जाता है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन के हर स्तर को प्रकाशमयी बनाना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी स्तर अंधकारमय रहेगा, तब तक हम अपने जीवन को संपूर्णता के साथ सत्य नहीं कर पाएंगे। दीपोत्सव में दीयों को पॉक में रखकर जलाया जाता है, इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन का प्रत्येक स्तर प्रकाशमयी हो जाए। अंधकार को प्रकाश ही मिटाता है और जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से ही मिटाना जा सकता है।

नुपुर तलवार की रिहाई का फैसला

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स बदली गई और फॉरेंसिक विभागों के अधिकारियों पर दबाव डाले गए। टीवी चैनलों ने भारत की प्रमुख जांच एजेंसी की अक्षमता और अदक्षता को लेकर खासा शोरगुल मचाया। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड का फैसला आया है। जस्टिस बीके नारायण और एके मिश्र ने भ्रष्टाचार-निरोधक सीबीआईअदालत, गाजियाबाद के अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश एस लाल के फैसले को खारिज किया।

सतीश पेडणेकर

सुनंदा पुष्कर (नीकराहा से राजनेता बने शशि थरूर की पत्नी) के हत्याओं का पता नहीं चल पाने के सदमे से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि आरुषि तलवार और हेमराज के दोहरे हत्याकांड से उसका सामना हो गया। ऐसा हत्याकांड जिसकी तत्पश्चात् आधी-अधूरी हुई। न अपराध स्थल को सील किया गया और न ही कर्म के वस्तुओं की जवबी की गई। इन हत्याओं के कारण अभी भी अज्ञात हैं। कभी आत्महत्या माना गया तो कभी हत्या।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स बदली गई और फॉरेंसिक विभागों के अधिकारियों पर दबाव डाले गए। टीवी चैनलों ने भारत की प्रमुख जांच एजेंसी की अक्षमता और अदक्षता को लेकर खासा शोरगुल मचाया। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड का फैसला आया है। जस्टिस बीके नारायण और एके मिश्र ने भ्रष्टाचार-निरोधक सीबीआईअदालत, गाजियाबाद के अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश एस लाल के फैसले को खारिज करते हुए डॉ. नुपुर तलवार और डॉ. राजेश तलवार को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ परिस्थितिजन्य सबूत भले हों लेकिन जांच एजेंसियां उनके अपराध में लित होने की ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजेश और नुपुर तलवार की रिहाई का फैसला सुनाते हुए सही ही कहा है: दृष्टान्त जब न अपने तरीके से गलत अनुमानों से भरे त्यों पर कहानी खड़ी कर ली और किसी फिक्क निर्देशक की तरह काम किया। खुद की भावनाओं के अनुरूप त्यों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। पूरे घटनाक्रम पर खुद अपनी कल्पना से परिस्थितियों का दायरा बना लिया और सीबी नजारे से फैसला भी सुनाया। कुछ ने तलवार दंपति की रिहाईको खुशी का अवसर बताया है। इसलिए कि तलवार दंपति के सामन्याय कोषा नहीं, क्योंकि वे मानते हैं कि राजेश और नुपुर तलवार ने अपनी बेटी को अपने नीकर हेमराज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर उसकी हत्या कर दी। कोई भी तर्क योग्य, लेकिन यह न्याय का मजाक ही है कि समूचे देश को सत्यकर देने वाले इस दोहरे हत्याकांड के वास्तविक अपराधी खुले घूम रहे हैं।

आरुषि के साथ वास्तविक न्याय तभी होगा जब सीबीआईऔर पुलिस हत्यारे को दबोच कर सीखों के पीछे डालें। अगर तलवार दंपति निर्दोष थे तो उन्हें द्रुतल कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बाद 2013 से ही जेल में क्यों रहना पड़ा? इतने वर्षों तक जेल में कलंकित, एकाकी और कैदी जीवन भोगने की भरपाईकोन करेगा? दूसरी ओर, यदि दीपों थे तो पर्याप्त प्रमाण के अभाव में उन्हें रिहा किया गया, न्याय कहा होगा। यह समूचा घटनाक्रम सार्वजनिक रूप से घटा, जिससे जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगता है। या

तो जांच एजेंसी बेहद लापरवाही बरतती दिखी या फिर जान-बूझ कर किसी की शै पर पूरे मामले को दबावी-छुपाती दिखी। बहरहाल, कारण कुछ भी रहा हो लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जांच ढेंगमा और पूरी तरह से नाकाम साबित हुई और यह इस बात की सीसाह है कि जांच के दौरान कभी भी चुक या नादानी नहीं की जानी चाहिए। जांच एजेंसी को अनेक समस्याओं के जवाब देने होंगे। 2008 में चौदह वर्षीय आरुषि और नीकर हेमराज को हत्या की गई थी। दो दिनों तक पुलिस ने घटनास्थल को सील नहीं किया। मॉरिया और आस-पड़ोस के लोगों समेत हर कोई वहां तक मटरासीली अंतर्गत में आ-जा रहा था। फोटो लेने की जाय, सबूत लेने के नाम पर महत्वपूर्ण वस्तुओं को छेड़-छुड़ कर लीट रहा था। यह सब दो दिनों तक चलता रहा। तब तकालीनी उपाधीक्षक केके गौतम घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस से छत्र की ओर जाने वाली खुन की लकीरों की पीछे करके को लका। पुलिस खुन को लकीरों का पीछे करते हुए खुर पहुंची तो वहां हेमराज का शव पड़ा गया। पुलिस के छात्रों ने घुस घटनास्थल पर नहीं लाता गए। उंगलियों के निशान नहीं उठाए गए। हेमराज का मोबाइल फोन जब नहीं किया गया। इन शुरुआती बातों पर ध्यान दिया गया होता तो उच्च न्यायालय को तलवार दंपति या अज्ञात हत्यारों को समुत्त के अभाव में रिहा नहीं करना पड़ता।

जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर मामला बिना सब साबित हो गया होगा। पुलिस जांच में पता चला कि नौ वर्ष बाद (मॉडिया दृष्टान्त समेत) भी तब यह है कि घटना के दिन मकान में जबन प्रवेश को बात सामने नहीं आई। मरने वालों के साथ अंतिम बार



जांचकर्ताओं को दूसरी टीम ने शक की खुद को तलवार दंपति की तरफ मोड़ते हुए सीबीआईकोर्ट में सबूतों के अभाव कहते हुए खोज रिपोर्ट पेश कर दी। बहरहाल, शुरू से तब राधा कि कोई तो है, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय को तलवार दंपति की महज इसलिए रिहा करना पड़ा है कि मामला सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो सका।

आरुषि को नौ वर्ष बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। जांच में लापरवाही या उच्च पदासीनों के चलते जांच आधी-अधूरी रह गई।

चलते चलते

वायु प्रदूषण

पर्व कब पटखों के शोर वाले पर्व में तब्दल हो गया, इसका अंदाजा प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर बढ़ने के बाद चला। पटखों से होने वाले ध्वनि और साधु प्रदूषण के चलते देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली-आंध्रपास के इलाकों में 1 नमबर तक पटखों की बिक्री को रोक लगाने का फैसला किया है। अदालत यह देखना चाहती है कि दीपावली के आसपास पटखों पर रोक से प्रदूषण के तहत में किन्हीं दीपावली के रोक से? देखा गया है कि दीपावली के बाद वायु और ध्वनि का प्रदूषण खतरनाक तत्तर बढ़ जाता है। पिछले साल दीपावली के दूसरे दिन पटखों की स्थिति किन्ती भयावह थी, यह किसी से छुपा नहीं है। पर्यावरण को लेकर हम किन्ते संजोदा हैं, यह भी जनाजाहिर है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत के निर्णय पर अमल करने के

मुदा

चुनाव की रणभेरी बज

प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पिछले कुछ महीनों से जनता के बीच ताल ठोक रही बीजेपी और कांग्रेस अब अपनी अपनी कुर्सी बचाव विस्तार विजय में जुट गई हैं। एक तरफ जहां चुनाव की प्रभावी और असमर्थ पण्णित पर काम हो रहा है तो वहीं जूनिक उम्मीदवारों के नामों पर गहन चर्चा हो रही है। नामांकन का काम 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लड़ाका सिवासी गणगणमयी चरम पर है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही शुक्रआती चुनौती अपने अपने उम्मीदवार फलन करने को लेकर है। प्रदेश में इस बार “न्यू हिमाचल विज् नुजिन” की बयार है। बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह “न्यू इंडिया” के निर्माण में दिन-रात एक किए हुए हैं, क्या उसी तर्ज पर “न्यू हिमाचल” का निर्माण भी होगा। बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस पर पहाड़ी मुठभेड़ को विकास की राह पर आगे ले जाने का रोडमैप तैयार है। हिमाचल में पिछले पांच साल से कांग्रेस का राज है। लिलासा सत्ता विरोधी लहर का सबसे ज्यादा खराब उसे ही। वहीं केंद्र को मोदी सरकार और अंतिम शाह का दावा है कि पिछले तीन सालों में जनता के कल्याण के लिए 106

योजनाएं लांच कीं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ हिमाचल की जनता तक किन्ता पहुंचा इसके अकाल का कोई पैमाना नहीं है। इस कारण दोनों ही पार्टियों पर सार सरोकार से जुड़े चुनावी मुद्दे उठते और उन्हें अपने-अपने घोषणा-पत्र में प्राथमिकता देने का दावब है। हिमाचल विधान सभा चुनाव में इस बार भी सबसे संवेदनशील मुद्दा धुवा सरोकार ही है। प्रदेश में 29.5 प्रतिशत युवा मतदाता हैं। इनमें से 40,567 युवा पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 12.5 लाख नौवयान ऐसे हैं, जिनकी उम्र 18-19 साल की है, जबकि 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 12.3 लाख है। वहीं, प्रदेश के मेथवी युवाओं को बेहतर शिक्षा और नौकरी के अवसर आज भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का र ख कास पड़ता है। औद्योगिक नगर नारायण, बंदी और बरोटीवाला को नाराज कर देता है। जिनमें उद्योग धंधे का के ब्यावर्क हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार ने कोशल विकास सत्ता सौते बेरोजगारी भुजा और अन्य योजनाओं से युवाओं के लिएरोजगार सौते के केंद्र पर्याप्त किए हैं। प्रदेश में सूख, लुप्त और मध्यम उद्योग, “न्यू इंडिया” और विशेष औद्योगिक पेंकज से भी रोजगार के हालात नहीं सुधरे हैं। आईआईटी, आईआईआईटी और एमए को सीमित प्रतीत की जनता की मिली है। अगर बेरोजगारी को बंदी भीड़ के आगे बस कुछ “ऊँट के मुँह में जौ” समान साबित हो रहा है। प्रदेश में पहली बार महिला सुविधा बड़ा सिवासी मुद्दा बन

विसंगति की समाप्ति

आभा स्नामी

सूर्यम कोर्ट ने इराफांमौ महत्त्व का फैसला दिया है। इससे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने का कानून अधिक सुसंगत बनेगा। साथ ही बाल विवाह के प्रचलन के कारण समाज में जारी विसंगति पर लगाने लगाने में मदद मिलेगी। यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कों के साथ यौन संबंध बनाने सींगी जुर्म है। लेकिन यदि वह लड़कों विवाहित हो और 15 साल की हो चुकी हो, तो उसके पति को उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाने की छूट मिल जाती थी। यह एक अवांछित विसंगति थी। अगर 18 साल की उम्र तक कोई लड़की यौन संबंध की सहमति देने योग्य नहीं मानी जाती, तो फिर उसका विवाह हो जाने से भी इस हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह भारत में विवाह की वैधानिक उम्र 21 साल है। 18 साल की लड़कियों के लिए 18 साल है। परिपूर्णण स्थार्थ यह है कि इस कानून का खूब उल्लेख होता है। लेकिन अब 18 साल से छोटी किसी भी लड़की से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाएगा, बंदे ही वो युवती भी हो कि क्यों न हो। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले का अर्थ है कि बाल विवाह के खिलाफ पहले से मौजूद प्रावधानों के अलावा एक और कठोर प्रावधान अमल में आ गया है। अब यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे इन प्रावधानों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित कराएं। वैसे अनुभव यही है कि सामाजिक परंपरा और आम संस्कृति से जुड़े मामलों में कानून या न्यायिक निर्णय पूर्ण प्रासन्नशील नहीं हो पाते। खासकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने से संबंधित वैधानिक प्रावधान भारतीय समाज में अपने उद्देश्य को अथवा तबूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बाल विवाह और दहेज प्रथा का जारी रहना इस बात की मिसाल है। प्रधान न्यायाधीशजस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस तथ्य का जिक्र किया कि आजादी के 70 साल बाद भी बाल विवाह सामाजिक व्यवस्था बंधे हुए है। ऐसा क्यों है, इस पर पूरे समाज को उत्सव-मनन करना चाहिए। रसअसल, असली चुनौती सामाजिक मानसिकता को बदलने की है। इसके लिए समाज सुधार और जन-जागरूकता के व्यापक आंदोलनों की आवश्यकता है। अफसोस की बात यह है कि आजादी के बाद समाज सुधार के महत्त्व की पुला दिया गया। अगर, भारतीय दंड संहिता की (दुष्कर्म विरोधी) धारा 375 में 15 साल से ऊपर की विवाहिताओं से पति द्वारा यौन संबंध बनाने की छूट बरकरार रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही इस मामले में कानून निर्माताओं के विवेक पर स्वावल खस किया। सरकार के लिए समाज पर न्यायालय द्वारा की गई समीक्षा से सही निर्णय पर पहुंचना जा सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 2जी सेक्मड के निर्णय में किया था। सरकार ने कानून में संशोधन करके अफसरों को टिप्पुलत का प्रमुख बनाने का दावा खोल दिया है। मनचाहे अफसर को नियुक्त करके सरकार टिप्पुलत द्वारा सरकार के निर्णयों की समीक्षा पर रोक लगाना चाहती है, जो दीर्घकाल में सरकार के निर्णयों की ही हानिपद होगा जैसा नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा भी है। वर्तमान सरकार ने व्यवस्था बर्बाद है कि अब मौलिक नीति संहिता जारी पापरीणी द्वारा मुद्रा नीति निर्धारित की जाएगी। इसमें तीन सदस्य रजवर्ग बैंक के अधिकारी होंगे और तीन सदस्य समाज द्वारा नामित होंगे। बुकिंगम इंस्टीट्यूशन द्वारा कहां गया, यह व्यवस्था देश के दीर्घकालीन विकास के लिए ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी पर देश को भरसा है। इस भरसे को लीपबुद्ध करने के लिए सरकार को हर नागरिक और प्रत्येक मनुष्य को निज की निज की दृष्टि से देखना होगा, अन्याय हॉिदरा गांधी की तरह वह सरकार भी देश को दीर्घकालीन विकास को पटरी पर नहीं ला सकेंगी।

मार दी, जिससे गुस्साए अपराधी ने पिस्टल के बट से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। लड़की और उसके घर के लोगों के चिल्लाने पर ग्रामीण जमा हो गए और दो अपराधियों को पकड़ लिया।

स्वतन्त्राधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्प्लेक्स सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तामीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री गम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसग सूरत 394210 से मुद्रत. फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamav@gmail.com